

सम्पादकीय

यह तो नाइंसाफी है!

देश भर की जिला अदालतों और निचली अदालतों में 3.9 करोड़ मामले लंबित हैं। हाईकोर्ट में 58.5 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 69000 मामले लंबित हैं। इसकी एक बड़ी वजह जजों की कमी भी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के क्रम में उत्तर प्रदेश की अदालतों में लंबित पड़े मामलों की जो तस्वीर उभरी है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इससे पता चलता है कि यूपी में किसी निचली अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया कोई व्यक्ति अगर हाईकोर्ट में अपील करता है, तो उसे इंसाफ के लिए औसतन 35 साल इंतजार करना पड़ता है। यानी अगर किसी पर गंभीर धाराओं के अपराध दर्ज हैं, जिनमें जमानत मिलना मुश्किल होता है तो बहुत संभव है उसे फैसला आने से पहले बरसों बरस जेल में ही बिताना पड़ जाए। यह मामला दरअसल सुप्रीम कोर्ट पास कई याचिकाओं के रूप में आया, जिनमें अदालत से गुहार लगाई गई थी कि वह दखल देकर बरसों से (कई मामलों में तो 14 बरस से भी ज्यादा) जेल में पड़े सुनवाई का इंतजार कर रहे कैदियों को जमानत देने की राह खोला। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों से साफ होता है कि हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ बैचों के पास इस समय 1,83000 आपराधिक अपीलें लंबित हैं। पिछले पांच वर्षों में कोर्ट ने 16,279 आपराधिक अपीलें निपटाई हैं, लेकिन इसी अवधि में 41,151 नए अपीलीय मामले आ गए हैं।

आपाराधिक अपीलीय मामले निपटाने की कोर्ट की रफतार 18 फीसदी बढ़ाई जाती है। इस मामले में भले ही बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की अदालतों की हो रही हो, देश के अन्य राज्यों में भी कोई बेहतर हालात नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश भर की जिला अदालतों और निचली अदालतों में 3.9 करोड़ मामले लंबित हैं। हाईकोर्टों में 58.5 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 69000 मामले लंबित हैं। इसकी एक बड़ी वजह जजों की कमी भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात करें तो वहां जजों के कुल 67 पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसा ही अन्य कोर्टों में भी है। इन पदों को जल्द से जल्द भरने का इंतजाम भी होना चाहिए, शीघ्र सुनवाई और जल्द फैसले सुनिश्चित करने से जुड़ी अन्य सिफारिशों पर अमल के प्रयास भी साथ-साथ चलने चाहिए, लेकिन इन सबसे पहले जेलों में अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे कैदियों को तकाल राहत देने की व्यवस्था होनी चाहिए। यूपी सरकार की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जघन्य अपराध और आदतन अपराध से जुड़े मामलों को छोड़कर आजीवन कैद के मामले में दस साल और अन्य मामलों में तय सजा की आधी अवधि जेल में गुजार चुके कैदियों को जमानत दी जा सकती है। इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि राहत देने का ऐसा कोई फॉर्म्युला सिर्फ यूपी तक सीमित न रहे। चूंकि समस्या पूरे देश की है, इसलिए इलाज के दायरे में भी पूरे देश को शामिल किया जाना चाहिए।

नीरज कौशल

देश में आरक्षण और जातिवार जनगणना को लेकर बहस नए सिरे से तेज हो रही है। ऐसे में जो असल में पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें चौकन्ना हो जाना चाहिए क्योंकि जो कथित बड़ी जातियां हैं, वे केंद्र और राज्य सरकारों की दृष्टि लिस्ट में घुस आई हैं। वे उस आरक्षण का लाभ ले रही हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए। ओबीसी की राज्यों और केंद्र सरकारों की लिस्ट में अपर कास्ट की घुसपैठ रातोरात नहीं हुई। मंडल कमिशन ने सरकारी नौकरियों में 27 फौसदी आरक्षण की सिफारिश की थी। वीपी सिंह सरकार ने जब वह सिफारिश लागू की, लगभग तभी से दृष्टि लिस्ट में अपर कास्ट की घुसपैठ शुरू हो गई। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में आरक्षण के लिए राज्य की जो दृष्टि लिस्ट है, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़ी कई जातियां हैं। इनमें गौड़ सारस्वत ब्राह्मण भी हैं। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण दरअसल सारस्वत ब्राह्मणों का हिस्सा हैं। मेरी मां बताती थीं कि समाज में सारस्वत ब्राह्मणों का स्थान इतना ऊंचा था कि उन्हें पूजने लायक माना जाता था। तमिलनाडु और केरल में अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट देखें तो पता चलता है कि सौराष्ट्र ब्राह्मण जैसी ऊंची जातियां उनमें शामिल हैं। जाति व्यवस्था में अपने दर्जे के चलते ब्राह्मणों का जीवन दूसरों के मुकाबले आसान रहा। व्यवसाय के रूप में उनका काम था धर्म-कर्म की चीजें पढ़ना-पढ़ना और पूजा-पाठ वर्गैरह करना-करना। इसके बदले में उन्हें खाने-पीने की चीजें, कपड़े और दूसरे उपहार दिए जाते थे। रहने का इंतजाम भी या तो मंदिर में या उसके आसपास कर दिया जाता था। मंडल कमिशन के मुताबिक, दृष्टि उन्हें माना जाता है, जो सामाजिक और ईश्विक रूप से पिछड़े हैं। ऐसे में यह एक पहेली ही है कि ब्राह्मण कब, कैसे और क्यों सामाजिक

आर शांकिक रूप से पिछड़ हो गए। राज्यों का इंग्लिस्ट में राजपूत हैं। उत्तराखण्ड में लोधी राजपूत और पंजाब में कश्यप राजपूत। राजपूत का मतलब है राजा का बेटा। एक जाति के रूप में देखें तो राजपूतों ने कासदियों तक भारत के तमाम इलाकों पर राज किया। जाति क्रम में योद्धा और शासक के रूप में उनका दर्जा हमेशा सबसे ऊचा रहा। ऐसे में राज करने वाली जाति को 'पिछड़ा' कैसे कहा जा सकता है महाराष्ट्र में खुद को छत्रपति शिवाजी का वंशज बताने वाला मराठा समुदाय इंग्लिस्ट में आना चाहता है। राज्यों की इंग्लिस्ट में कई ऐसी जातियां हैं, जिनके पास अच्छी-खासी जमीन है। राजस्थान में पटेल समुदाय ऐसा ही है। जाट समुदाय भी इसी तरह का है। सबसे बड़ी विंडबुना कथित नीची जातियों के लिए। इनमें न केवल मराठा, बल्कि दलित शामिल हैं। खुद को लड़ाकों में बदलकर उन्होंने अपने ऐतिहासिक पिछड़पंड से पीछा छुड़ाया और शासक भी बने। मसलन, सिंधिया और गायकवाड़ फिर किसने हिमाकत की इन जातियों को इंग्लिस्ट बताने की

ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अच्छी-खासी जमीन रखने वाली जातियों के बीच इसका विवरण हमें दिया गया है।

कारण ही कई जातियां पिछड़ गईं। इन ऊंची जातियों ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई और जो रीति-रिवाज थेपे, उनके चलते असल धृण व हाथों से मौके छिन गए। इन असल धृण का जीवन छोटे-मोटे धृणों फंसकर रह गया। ऊंची जातियों ने सामाजिक, आर्थिक और पेशागत सीमाएं तय कीं और इन असल धृण को उन्हें पार नहीं करने दिया गया।

विध्यक का एकमत से पास किया। इस बिल ने राज्यों का एक आधिकार बहाल किया। अब वे तय कर सकते हैं कि धूंगी की उनकी लिस्ट में कौन जाति रहेगी, कौन नहीं। इससे एक नया बवाल शुरू होगा। ऊंची जातियां जोर लगाएंगी कि उन्हें धूंगी लिस्ट में रख दिया जाए। नेता वोटों के लिए उनकी बात मान लेंगे। धूंगी की लिस्ट राज्य के स्तर पर तैयार होनी ही चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कोई जाति किसी राज्य में पिछड़ी हो और दूसरे राज्य में न हो। लेकिन लिस्ट बनाने के लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्र संस्थाओं की जरूरत है, जो राजनेताओं के प्रभाव में न हो। साथ ही, क्रीमी लेयर वालों को भी लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। सुरीम कोर्ट की खलिंग भी यही है। वैसे भी जातियों की गणना का मसला काफी जटिल हो गया है। 1901 की जनगणना में बताया गया कि भारत में एक हजार 646 जातियां थीं। 1931 की जनगणना होने तक यह संख्या ढाई गुना बढ़ गई। बताया गया कि देश में 4 हजार 147 जातियां हैं। 1931 की जनगणना के बाद से देश में जातियों की संख्या एक हजार गुना बढ़ चुकी है। देश में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना पहली बार 2011 में कराई गई। उस जनगणना में जातियों, उप-जातियों, सरनेम, गोत्र, कुल आदि के रूप में 46 लाख कौटिगरी सामने आई। उस जनगणना में जातियों के बारे में जो ब्योरे दर्ज किए गए, उनमें आठ करोड़ से ज्यादा गलतियां हैं। राज्य सरकारों ने करीब पौने सात करोड़ गलतियां ठीक कर दी हैं, लेकिन अब भी डेढ़ करोड़ जस की तस हैं। हमें लेकिन यह नहीं पता कि सरकारी अधिकारियों ने कुछ ब्योरों को किस आधार पर गलत माना और किस आधार पर उन्हें दुरुस्त किया। इस साल 10 अगस्त को आखिरकार सरकार ने 2011 की जनगणना को अशुद्ध करार दिया। उसने बाद किया है कि हर दस साल पर होने वाली जनगणना जब पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद एक और जातिवार जनगणना कराई जाएगी। भारत सरकार को लेकिन यह पूछाना चाहिए कि जातिवार जनगणना की जरूरत क्या है और क्या उसमें पक्षपात नहीं होगा।

कॉमन रुमः तमाशा बना दिया गया है नीरज चोपड़ा का

रूपेश रजन सिंह

सोने का महत्व और इसकी कद्र भारत ही समझता और करता है। हम चीनियों की तरह नहीं हैं, जिन्होंने 38 स्वर्ण पदक विजेता सहित कुल 88 पदक विजेताओं को स्वदेश लौटे ही क्वारंटीन कर दिया। हम तो एयरपोर्ट पर उतरते ही ऐथलीट के गले पड़ जाते हैं। उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। उसका इतना सम्मान करते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है। अन्य देशों के ऐथलीटों को हमारे ऐथलीटों से रखक होने लगता है। तोक्यो ओलिंपिक में भारत को ऐथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले जैवलिन थोअर नीरज चोपड़ा इसका जीता जागता उदाहरण हैं। नीरज ने सात तारीख को गोल्ड जीता और उसके बाद से मजाल है कि उन्हें अपने बारे में सोचने का भी वक्त दिया जाए। अगर कोई शक-ओ-शुबह है तो नीरज के पिछले कुछ दिनों का यह कार्यक्रम देख लीजिए। नीरज ने 7 अगस्त को गोल्ड जीता। इसके बाद से वह मीडिया से घिरे रहे। तोक्यो में ही एक के बाद एक इंटरव्यू हुए। 8 तारीख को समाप्त समारोह में शामिल हुए। 9 को करीब छह घंटे की हवाई यात्रा करके भारत लौटे। शाम को स्वदेश लौटने के कुछ घंटों बाद ही खेल मंत्रालय के एक सम्मान समारोह में शामिल हुए। एयरपोर्ट

से होटल तक के रास्ते में भी वह मीडिया व प्रशंसकों से घिरे रहे। 1 तारीख को ऐथ्लेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सम्मान समारोह में पहुंचे इसके बाद उन्हें तेज बुखार हो गया। 12 और 14 तारीख को इस कारबह पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो सके। लेकिन 14 की शाम राष्ट्रपति भवन में चाय के कार्यक्रम में वह मौजूद रहे। 15 अगस्त की सुबह से लाल किले पर मौजूद रहे। उसी शाम भारतीय ओलिंपिक्स संघ के कार्यक्रम में पहुंचे। 16 की सुबह प्रधानमंत्री नाश्ते पर मुलाकात की। 17 को उनके गांव में जलसा था, उसके लिए वह पानीपत पहुंचे। लेकिन तबीयत नासाज थी, उन्हें कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर निकलना पड़ा। खबर आई कि उन्हें कुछ देर के लिए पानीपत में अस्पताल भर्ती भी होना पड़ा। लेकिन 18 तारीख को फिर उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना पड़ा। उसी रात वह लखनऊ पहुंचे, अगले दिन यूपी सरकार के सम्मान समारोह में शामिल हुए। भारत पहुंचने के बाद नीरज का यह व्यस्त कार्यक्रम पढ़ते-पढ़ते शायद आप भी थक जाएं, लेकिन नीरज को थकने नहीं दिया गया। नीरज के बगल से गुजरा हर शख्स सोशल मीडिया के हर प्लैटफॉर्म पर उसके साथ की तस्वीर साझा कर अपना पहुंच और नीरज से अपनी नजदीकी का सबूत पेश कर रहा है। सम्मान समारोह के जरिए हर कोई नीरज की उपलब्धि में अपना भी योगदान साबित कर रहा है।

कर रहा है। फिलहाल सभी खेल प्रेमी बन गए हैं। हालांकि इस बीच कुछ फेडरेशन वाले खासकर शूटिंग फेडरेशन वाले नीरज के गोल्ड से अतिरिक्त खुश होंगे क्योंकि कुछ देर के लिए ही सही, उनकी नाकामियों से सभी का ध्यान हट गया है। तोक्यो ओलिंपिक्स के शुरुआती दिनों में निशानेबाजों की असफलता पर हाहाकार करने वाले आज नीरज के साथ एक फोटो खिंचवाने की होड में शामिल हो चुके हैं। सभी नीरज से मिलना चाहते हैं, सभी उनका सम्मान करना चाहते हैं, सभी उनसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन नीरज क्या चाहते हैं, यह कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि कार्यक्रम तो तय हो चुका है। फूल-मालाएं खरीदी जा चुकी हैं। अतिथि गणों को न्योता भेजा जा चुका है ऐसे में सम्मान तो नीरज को लेना ही होगा।

यहां सम्मान दिया नहीं, लादा जा रहा है। ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने की खुशी समझ आती है, लेकिन सम्मानित करने की होड समझ से परे है। नीरज ने देश का मान बढ़ाया है, हमें उनका आदर करना ही चाहिए, लेकिन हमें उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। फिलहाल, नीरज किसी अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने विदेश भी नहीं जा रहे, ऐसे में उन्हें कुछ दिन आराम करने और अपने परिवार संग समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह के जान-लेवा सम्मान समारोह को देख कहीं ऐथलीट भी अलिंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने से कठराने ना लग जाए।

अफगान मसला : सवाद की खिड़की का खुलना सुखद

राकेश अचल

भारत का रवैया सम्भवतः पारम्परिक विदेश नीति के अनुरूप होगा। भारत सरकार के पास एक मौका है जब वह विदेश नीति को लेकर अतीत में हुई अपनी गलतियों को सुधार ले। ऐसा सभी के साथ विचार-विनियम से ही सुमिक्षन होता है। याद रखना होगा कि इस समय हम अफगान मामले में अपनी ढपली से जो भी राग निकालेंगे उससे ही पूरे क्षेत्र में हमारे वैदेशिक रिश्तों का निर्धारण होगा। अपनी धून में चलने वाली नरेन्द्र मोदी सरकार ने देर से ही सही लेकिन अफगान मसले पर संवाद की खिड़की खोलकर समझदारी का काम किया है। खबर है कि केन्द्र ने अफगानिस्तान मामले पर 26 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक आहूत की है, जिसमें सभी को पड़ोसी मुल्क के ताजा हालात से वाकिफ कराया जाएगा। सरकार को यह फैसला करने में कोई दिन लग गए। अफगान मसले पर देश की चुप्पी को लेकर सब दूर बैठेनी थी, बैठेनी है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारत ने क्या सोचा है और क्या किया है सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने में व्यस्त थी। सुमिक्षन है कि इसी वजह से सरकार ने मैनून धारण कर लिया हो। अब लगता है कि सरकार भारतीयों को स्वदेश लाने के मिशन में कामयाब हो गई है, इसलिए इससे फारिंग होते ही सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। विपक्ष को लम्बे समय से शिकायत है कि सरकार तमाम मुद्दों पर न बात करती है नहीं पड़ता। गोदो मीडिया का काम कट-पेस्ट और उथार को सामग्री से छल जाता है। वैसे भी मीडिया की विश्वसनीयता अब पहले जैसी रही भी नहीं। अफगान मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति दस दिन में मीडिया के सामने दो बार आए, चीन के विदेश मंत्री भी बैठले लेकिन भारत ने मैनून रहना ही श्रेयस्कर समझा। अब सरकार की समझ को चुनौती तो नहीं दी जा सकती। हाँ, सवाल किये जा सकते हैं, जो किये गए। भले ही किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार सवालों से भागती है। सवाल चाहे संसद मैं किये जाएं या सङ्केत पर खड़े होकर- सरकार को नहीं पोसाते। अफगान मामले पर भी ढेरों सवाल किये गए लेकिन सरकार नहीं बोली क्योंकि उसे नहीं बोलना था। अच्छी और चौंकाने वाली खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम की जानकारी संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं को दे। इसी तारतम्य में केन्द्र सरकार ने 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत सरकार क्या कूटनीतिक कदम उठा रही है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। सभी को शायद याद हो कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने बहुत पहले ही संसद में अफगानिस्तान

तालिबान से डरते, उसके नाम से

डॉ. दीपक पाचपोर

A photograph showing a group of Taliban fighters in a rugged, mountainous terrain. Several men are standing, some holding rifles, while others are seated or standing behind them. They are dressed in traditional Afghan clothing, including turbans and ponchos. The background shows dry, rocky hills under a clear sky.

डॉ. दीपक पाचपोर

भारत सार्क देशों के समूह में सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण है। अतः उससे यह सहज अपेक्षा की जाती है कि वह तालिबान जैसे संगठनों का खुला विरोध करे क्योंकि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिये भी यह ज़रूरी है। भारत तो आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज उठाता रहा है। तालिबान संकट का संबंध भारत की सुरक्षा से है। जब हमारे देश के दोनों प्रमुख दुश्मन- चीन एवं पाकिस्तान तथा मित्र रहा रूस तालिबान के साथ खड़े दिख रहे हैं।



के मुद्दे पर बहस की मांग की थी लेकिन इस मांग को कोई तवज्जो नहीं गई क्योंकि मांग कंग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी की ओर से की गयी थी। सरकार यदि संसद के चलते अफगानिस्तान पर बहस कर लेती तो मुमुक्षिन हैं कि उसके ऊपर राजनीतिक हमले न हुए होते लेकिन बहस इस सरकार का चरित्र नहीं है। जब सरकार आठ महीने से अधिक वक्त आंदोलनरत किसानों से बहस नहीं कर रही है, तो फिर अफगानिस्तान टामामला तो एकदम ताजा है। केन्द्र सरकार की इस बात के लिए सराहना दें जा सकती है कि उसने बड़ी ही सुरक्षित तरीके से अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकांश भारतीयों को बाहर निकाल लिया है। सचमुच यह एक कठिन और तनाव का काम था। भारतीयों की सकुशल वापसी के बाद अब सरकार देश को अपनी भावी योजनाओं और रणनीति के बारे में बता सकता है। बीते कुछ सप्ताह में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। राजथानी काबुल समेत देश के कई प्रांतों पर तालिबान का 15 अगस्त नियंत्रण है। उसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय वहां फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स को सक्रिय किया गया था। अब तक भारत ने 730 लोगों टका अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। इनमें राजनयिकों के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इस अभियान के अमेरिका ने भी भारत की सहायता की। तालिबान की भार-भीमियाएं अब तक बदली नहीं हैं। तालिबान अभी भी धर्मकी भरी भाषा में बात कर रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने एक बयान जारी किया और चेतावनीपूर्ण

में पहले ही आगे बढ़कर बयान देना चाहिये था। मुख्य कारण तो यह है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। वहां इस्लाम धर्म के उद्धर के पहले बौद्ध धर्म व बोलबाला था जो दोनों देशों को एक सूत्र में पिरोता है। वहां के नव्यार्थिक चरित्र के बाद भी नागरिक स्तर पर दोनों देशों के संबंध बहुत रहे हैं। खासकर, वहां के हिन्दू एवं सिख लोगों की उपस्थिति बहुत चलते। फिर, अफगानिस्तान की वर्तमान हालत के लिये मुख्य रूप महाशक्तियां जिम्मेदार हैं- अमेरिका एवं रूस। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही गुरु निरपेक्षता की राह पकड़ी थी। एक तरह से वह 125 से ज्यादा देशों का नेतृत्व करता रहा है जो किसी खेमे के सदस्य नहीं हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रिजो (मार्शल) टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासर के साथ मिलकर गुरु निरपेक्ष आंदोलन (एनएम-एनएम-को खड़ा किया था जो दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका एवं सोवियत रूस के बीच वर्षों तक जारी रहे शीत युद्ध के बीच भी बढ़ता रहा विश्व नेतृत्व की हसरत के चलते हाल के वर्षों में नरेन्द्र मोदी ने नाम बदला कर दिया है। अब हमारी वैदेशिक नीति का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सौहार्द, परस्पर सामंजस्य एवं विश्व शांति नहीं वरन् अपने कुछ मिलकर को संपन्न करने और बड़े देशों को खुश करने के लिये हथियार खरीदार और पूंजी निवेश आमंत्रित करने तक का रह गया है। आतंकवाद एवं पड़ोसी देशों का भय दिखाकर आम जनता की मूलभूत सुविधाओं भारी कटौती करते हुए मोदी सरकार पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाणे पर असलहा खरीद रही है। पूंजीवाद को प्रश्न्य और बढ़ावा देने के कारण हम कुछ बड़ी ताकतों के पिछलगूँ बन गये हैं। अगर हम नाम के अब भी अगुवा होते तो ऐसी स्थिति में न केवल ऊंची आवाज अपनी बात कह सकते थे बल्कि अपनी अंतरराष्ट्रीय साख के चलायद हस्तक्षेप करने की भी हालत में होते। जहां भी मानवीयता पीड़ित होती रही है, बड़े देशों से डरे बगैर भारत ने आवाज बुलन्द बना दी है और यथाशक्ति सहायता भी पहुंचाई है।

लहजे में कहा कि नाटो फोर्स 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट से नियंत्रण छोड़े और अपने देश लौट जाए। अफगानिस्तान से दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि अगस्त के अंत तक काबुल से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया जाएगा। यदि विदेशी अफगानिस्तान में रह गए तो आगे उन्हें निकालना कठिन हो जाएगा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर केन्द्र सरकार को सबकी सलाह से फैसला लेना चाहिए ताकि बाद में उसे अपनी आलोचना न सुननी पड़े। अफगानिस्तान की नई सरकार के प्रति भारत सरकार का रुख पूरे क्षेत्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। सारी दुनिया की नजर भारत पर है। भारत का रैया सम्भवतः पारम्परिक विदेश नीति के अनुरूप होगा। भारत सरकार के पास एक मौका है जब वह विदेश नीति को लेकर अंतीम में हुई अपनी गलतियों को सुधार ले। ऐसा सभी के साथ विचार-विनिमय से ही मुमकिन होता है। याद रखना होगा कि इस समय हम अफगान मामले में अपनी ढपली से जो भी राग निकालेंगे उससे ही पूरे क्षेत्र में हमारे वैदेशिक रिश्तों का निर्धारण होगा। अफगान के बहाने चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ ही हमें अमेरिका से अपने रिश्तों की भी समीक्षा करना होगी और यह काम बहुत आसान नहीं है। अफगानिस्तान में हुई उथल-पुथल का जितना खिमियाजा अमेरिका को भुगताना पड़ेगा वह तो जागजाहिर है लेकिन हम पर इसका जो असर पड़ने वाला है उसका आकलन किया जाना अभी शेष है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत की खिड़की के खुलने से इस आकलन में मदद मिलेगी।

टोट में छिपते लोग

है। अतः उससे यह सहज अपेक्षा की जाती है कि वह तालिबान जैसे संगठनों का खुला विरोध करे क्योंकि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिये भी यह ज़रूरी है। भारत तो आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज उठाता रहा है। तालिबान संकट का संबंध भारत की सुरक्षा से है। जब हमारे देश के दोनों प्रमुख दुश्मन- चीन एवं पाकिस्तान तथा मित्र रहा रूस तालिबान के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो भारत को आवाज उठाना लाजिमी है। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने अब तक इस घटना को लेकर अपना रवैया साफ नहीं किया है क्योंकि इस समस्या के बे ही दोषी हैं। नई अफगानी सरकार को मान्यता देना लोकतांत्रिक रूप से विकसित इन देशों के लिए मुश्किल है क्योंकि उन्हें अपनी जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इन स्थितियों को देखते हुए लगता है कि भारत कुछ कहने या करने के लिए बड़े देशों का मूँह ताक रहा है जो एक शक्तिशाली तथा लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हमारे देश के लिए सर्वथा अनुचित है। फिर, वह इस समय (एक माह के लिये) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी है इसलिये उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी बढ़ी हुई है। वहां मानवाधिकारों की रक्षा और शांति की अपील तो वह कर ही सकता है। सरकार की चुपी के बीच सत्ताधारी पार्टी समर्थित एक वर्ग ऐसा है जो तालिबान के नाम पर भयादोहन में बिन सौंपी गई ड्यूटी बजाने में व्यस्त हो गया है। सोशल मीडिया पर वह लोगों को डरा रहा है कि अगर मोदी न रहे तो तालिबान भारत भी आ धमकेगा। वह यह साबित करने पर तुला हुआ है कि अगर भाजपा की सरकार न रहती तो अब तक वह हमारे देश पर कब्जा कर चुका होता। यह आपदा में अवसर तलाशने जैसा ही है। संभवतः इस मुद्दे को 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव हेतु अभी से पकाया जाने लगा है। तीसरी श्रेणी है इस मुद्दे की आड़ में छिपने वालों की। पार्टी व उसके समर्थकों को अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये एक नई ओट मिल गई है। अफगानिस्तान संकट ने तालिबान से डरने, उसके नाम पर डराने और उसकी ओट में छिपने वालों को उघाइकर रख दिया है।

